सं म्रो वि./जी.जी.एन./55-83/58341. —चूं कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि एम्.डी.म्रो. (म्रोप्रेशन) एच एस.ई.बी., नागल चौधरी, जिला महेन्द्रगढ़, के श्रमिक श्री मनी राम तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है:

भीर चूं कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्विष्ट करना वांछनीय समझते हैं:

इसलिए, श्रव, श्रीद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा श्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा तरकारी श्रिधिसूचना सं० 5415-3-244-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए श्रिधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त श्रिधिनियम की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीटाबाद को विवादशस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला क्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उन्त प्रवन्त्रकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादशस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रथवा सम्बन्धित मामला है:—

न्या श्री मनी राम की प्रेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि/जी.जी.एन./108-83/58348 -चूं कि इरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज जय भारत डायरी म्रलवर रोड, सोहना, गुड़गांवा के श्रमिक श्री राम फल तथा उसके प्रबन्धकों के भध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई भौद्योगिक धिवाद है;

श्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं:

इसलिए, घव, श्रोद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा श्रिधिन्त्रना का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रिधिन्त्रना सं. 5415-3-श्रम-68/ 15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए श्रिधिस्त्रना सं० 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त श्रिधिनियम की धारा 7 के श्रिधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादशस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मीचे लिखा मामला न्यायनिणंय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रीमक के बीच या तो विवादशस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रयवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री राम फल की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक हैं ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं शो.वि./जी.जी.एन./109-83/58355. - चूं कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज इंडो हिवस टाईम लि., दिल्ली गुड़गांवा रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्री गुरदियाल सिंह राठोर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है;

भीर चूं कि इरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, ग्रव, ग्रीधोगिक विवाद ग्रिविनयम, 1947 की धारा 10 की उपद्यारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई गिक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाण के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रविसूचना सं० 5415-3-241-68/ 15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए, श्रविसूचना सं० 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त प्रविनियम की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदावाद को विवाद ग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रिमिक के बीच था तो विवाद श्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रथवा सम्बन्धित मामला है:---

क्या श्री गुरेदियाल सिंह राठोर की रोबाशों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकतार है ?

सं. म्रो.वि./रोहतक/190-83/58 369.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० ए.के.म्राई. इंटरनैशल प्रा॰िल॰, बहादुरगढ़, के श्रीपक श्री रामा कान्त तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रीद्योगिक विवाद है:

श्रीर चूंकि हस्याणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, अौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिरितयों का प्रयोग कृरते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641--1-श्रम-70/32573, विनांक 6-11-1970 के साथ पठित सरकारी श्रधिसूचना सं. 3864-ए एस.श्रो. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8-5-70 द्वारा उक्त श्रधिनियम की घारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिग्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है:—

क्या श्री रामा कान्त की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं श्रो.वि/पानीपत/21-83/58376. — चूंकि राज्यपाल, हिर्याणा की राय है कि मैसर्ज दी पानीपत कोपरेटिव भूंगर मिल्ज लि., डिस्ट्रीलरी यूनिट, पानीपत, के श्रमिक श्री शमशर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई ग्रीधोगिक विवाद है;

भौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अव, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपवारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियागा के राज्यपाल इतके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रवन्धकों के मध्य न्याय-निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं:---

क्या श्री शमशेर सिंह की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० श्रो. वि./करनाल/53-83/58403. --चूंकि राज्यपाल, हिरियाणा की राय है कि नगरपालिका, इन्द्री के श्रिविक श्री राम कुमार गर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई ग्रोधोणिक विवाद है;

, ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ध) द्वारा प्रदान की गई शिक्त्यों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन श्रीवोगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रवन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री राम कुमार की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं श्रो.वि./एफ.डी.-2/142-83/58416.—चूंकि राज्युपाल, हरियाणा की राय है कि मैसर्ज कालिन्दी इन्टरप्राईजिज प्लाट नं 0 28, सैक्टर-25, वल्लवगढ़, के श्रमिक श्री टूवर चौहान तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई श्रोद्योगिक विवाद है;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन औद्योगिक अधि-करण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रवन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री ट्वर चौहान की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं शो वि व / एफ.डी. / 127-83/58437. — चूं कि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मैसर्ज भारत इन्टरप्राईजिज प्लाट नं 17, सैनटर-6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राज सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित भामले के सम्बन्ध में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

भौर चूं कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायितर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिए, भव, भौद्योगिक विवाद धरिविषम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (!) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शिक्तयों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा इक्त ग्रिधिनियम की धारा 7-क के भिष्ठीन भौद्योगिक ग्रिधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामने श्रीमक तथा प्रवन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट केरते हैं:—

क्या ब्री राज सिंह की सेवाझों का समापन स्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो व<mark>ह किस राइत का</mark> हकदार है ?